Demands	Action taken
(4) Supply of uniform to certain new categores, supply of woollen jersey to patrolling khalasies deployed on oil pipelines, increasing chappal allowance from Rs. 35 to Rs. 50 per annum to he employees who were paid this allowance.	These matters are generally discussed by the Port Trust Authorities with the representatives of unions in order to find out solutions through mutual discussions .
(5) Providing promotional avenues to the diploma hoders (cil) to the post of executive Engineers in theratio of 1:1 with graduate civil engineers.	Government have already issued guidelines on this question and the Ports have been ad-advised to pesolve this issue inaccordance with the guidelines

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बसें चलाने के लिए गैर-सरकारी बस चालकों को परमिट दिया जाना

2574. **डा० अबरार अहमद :** क्या जल-भतल परिवहन मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर बसें चलाने तथा विभिन्न राज्यों की राजधानियों को परस्पर जोड़ने के लिए गैर सरकारी बस चालकों को राष्ट्रीय परमिट देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा ऐसे परमिट कब तक दे दिए जायेंगे ; और

(ग) क्या यह सच है कि फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चलाने के लिए गैर सरकारी बस चालकों को कुछ राष्ट्रीय परमिट पहले ही दिए जा चुके हैं, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार, केवल माल वाहनों को ही राष्ट्रीय परिमिट दिए जाते हैं । जहां तक बसों का संबंध है, राज्य परिवहन प्राधिकरणों को, व्यक्तिगत संपत्ति पर पाबंदियों के अध्यधीन अंतर्राज्यीय और अतः राज्यीय प्रावधानों के लिए परमिट प्रदान करने का अधिकार दिया गया है । इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 88(9) तहत कोई भी प्राइवेट बस आपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक परमिट ले सकता है । ऐसे परमिट कितने भी राज्यों के लिए वैद्य हैं और यह सख्या आवेदक की पसंद के तीन राज्यों से कम नहीं होगी ।

Handing over of DTC to Delhi Administration

2575. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL :

SHRI SHANTI TYAGI :

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government propose to hand over the Delhi Transport Corporation to the Delhi Administration ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the losses in DTC are mounting day by day ; and

(d) what is the extent to which its losses would come down after handing over the same to Delhi Administration ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) The proposal to hand over Delhi Transport Corporation to Delhi Administration has been deferred.